[2022] 18 एससीआर 449

मीना देवी

बनाम

नुनु चंद महतो @ नेमचंद महतो और अन्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 7255)

(अक्टूबर 13, 2022]

[न्यायमूर्तिगण संजीव खन्ना और जे. के. माहेश्वरी]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 140, 166 को पढ़ा जाए धारा 171 के साथ - मुआवजा - मोटर दुर्घटना में 12 वर्षीय लड़के की मौत में मुआवजा में वृद्धि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने 1,50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे दावा याचिका के मूल्य से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: दावा याचिका में किए गए कम मूल्यांकन, यदि कोई हो, दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा देने में बाधा नहीं होगी - ट्रिब्यूनल/अदालत को चाहिए 'न्यायसंगत' मुआवजा प्रदान करें जो रिकॉर्ड पर पेश किए गए साक्ष्य पर भरोसा करते हुए तथ्यों में उचित है - तथ्यों पर, मुआवजे की राशि न केवल और उचित गणना को देखते हुए - मृतक की मां के मौखिक बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक एक प्रतिभाशाली छात्र था, जो एक निजी स्कूल में पढ़ता था, इस प्रकार, भविष्य की संभावना सहित अनुमानित आय को 30,000/- रुपये के रूप में स्वीकार करने और 15 के गुणक को लागू करने पर, निर्भरता की हानि 4,50,000/- रुपये आती है और पारंपरिक शीर्षों में 50,000/- रुपये जोड़ने पर, मुआवजे की कुल राशि 5,00,000/- रुपये होगी - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे में 3,00,000/- रुपये की वृद्धि की गई है।

किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और अन्य (2014) 1 एससीसी 244: [2013] 10 एससीआर 793 - पर भरोसा किया गया।

आर.के. मलिक और अन्य बनाम किरण पाल और अन्य (2009) 14 एससीसी 1: [2009] 10 एससीआर 87; सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121: [2009] 5 एससीआर 1098; लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2001) 8 एससीसी 197: [2001] 1 अनुपूरक एससीआर 578; एम.एस. ग्रेवाल और अन्य बनाम दीप चंद सूद और अन्य (2001) 8 एससीसी 151: [2001] 2 अनुपूरक. एससीआर 156; कुरवन अंसारी @ कुरवन अली और एक अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और एक अन्य (2022) 449 - संदर्भित

1 एससीसी 317; नागप्पा बनाम गुरदयाल सिंह व अन्य (2003) 2 एससीसी 274: [2002] 4 अनुपूरक. एससीआर 499 - संदर्भित।

टैफ वेले रेलवे बनाम जानकिंस 1913 एसी 1 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

[2009] 10 एससीआर 87 संदर्भित कंडिका 4

[2013] 10 एससीआर 793 भरोसा किया गया कंडिका 4

[2009] 5 एससीआर 1098 संदर्भित कंडिका 4

[2001] 1 अनुपूरक. एससीआर 578 संदर्भित कंडिका 9

[2001] 2 अनुपूरक. एससीआर 156 संदर्भित कंडिका 9

(2022) 1 एससीसी 317 संदर्भित कंडिका 10 कंडिका 10

[2002] 4 अनुपूरक. एससीआर 499 संदर्भित कंडिका 13

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 की सिविल अपील संख्या 7255।

2013 के एमए संख्या 16 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.10.2018 से।

डी. पी. चतुर्वेदी, अनुज वर्मा, रमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता - अपीलकर्ता के लिए।

अनूप कुमार , श्रुति सिंह , अनुराधा मुतातकर अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी

अनुमति दी गई।

2. वर्तमान मामले के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि बच्चा, अर्थात्; बांकी बिहारी, दुर्घटना की तारीख अर्थात 29.7.2003 को लगभग 12 वर्ष की आयु में, अपने घर के सामने खेलते समय, कमांडर जीप द्वारा घायल हो गया था, जिसका पंजीकरण नं. जे.एच.-11ए 6894 था और धनबाद के एक अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप के लिए, "एम.वी.अधिनियम") की धारा 171 के साथ पठित धारा 140, 166 के तहत एक दावा याचिका अपीलकर्ता द्वारा ब्याज के साथ 2,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी, जो मृतक बच्चे की मां है।

3. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गिरिडीह (संक्षेप में, "एम.ए.सी.टी.") ने एकमुश्त 1,50,000/- रुपये का मुआवजा दिया। 2013 की विविध अपील संख्या 16 दायर करके इस तरह के मुआवजे की अपर्याप्तता पर सवाल उठाते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने दावा याचिका में किए गए दावे के मूल्य के बराबर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी।

4, इस तरह के मुआवजे के अनुदान की पर्याप्तता पर वर्तमान अपील दायर करके सवाल उठाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने "आर्थिक" और "गैर-आर्थिक" हानि के शीर्ष में राशि का आकलन करने में गलती की है। एम.ए.सी.टी और उच्च न्यायालय ने भावी खुशी की हानि शीर्ष और अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत कोई राशि प्रदान नहीं की है और निर्भरता की हानि शीर्ष के तहत दी गई राशि अपर्याप्त है। इसलिए, मुआवजे में वृद्धि की जानी चाहिए। आर.के. मलिक और अन्य बनाम किरण पाल और अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2009) 14 एससीसी 1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखते हुए यह आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे की गणना करते समय भावी संभावना को जोड़े बिना मृतक की कल्पित आय की कम मात्रा का आकलन करने में त्रुटि की है। किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और

अन्य (2014) 1 एससीसी 244 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है जिसमें एम.वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट 15,000/- रुपये के स्थान पर भविष्य की संभावनाओं सहित 30,000/- रुपये को नोशनल आय के रूप में मानते हुए और गुणक को लागू करने के निर्णय में निर्दिष्ट गुणक को लागू करने की गणना की गई है सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी। 121. आगे यह तर्क दिया गया है कि मृत्यु के मामले में, मुआवजे की उचित राशि ब्याज के साथ अनुमत के रूप में दी जानी चाहिए। यह आग्रह किया जाता है कि दावे का मूल्यांकन न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के लिए सारहीन है, हालांकि उच्च न्यायालय ने दावा याचिका के मूल्यांकन के बराबर मुआवजे को प्रतिबंधित करने में त्रुटि की।

5. श्री अनूप कुमार और सुश्री अनुराधा मुटकर, अधिवक्ताओं ने क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से वकालतनामा दायर किया है। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया था।

6. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि एम.ए.सी.टी. और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा उचित और उचित है, हालांकि दो न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अपील खारिज करने योग्य है।

7. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और निष्कर्षों के अवलोकन के बाद, बीमा कंपनी की देयता विवाद में नहीं है और दावेदार द्वारा केवल मात्रा पर सवाल उठाया जाता है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 4 - बीमा कंपनी की देयता के बिंदु पर, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को मंजूरी देते हैं।

8. इस मामले के तथ्यों में मुआवजे की गणना पर लौटते हुए, एक बच्चे की 12 साल की उम्र में अपने घर के सामने खेलते समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह नेहरू अकादमी, गिरिडीह रोड, जामताड़ा, डुमरी में 5 वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हालांकि यह देखना आवश्यक है कि मुआवजे की गणना कैसे की जा सकती है। उसकी मां द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृत बच्चा एक प्रतिभाशाली था कक्षा 5 का छात्र और यदि वह दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अधिकारी बन जाता। उक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, मुआवजा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

9. आर.के. मलिक(ऊपर) के मामले में यमुना नदी में स्कूल बस में सवार 29 बच्चों की डूबने से मौत नवंबर, 1997 में एक सड़क दुर्घटना में पुल की रेलिंग तोड़कर वहां के नदी में गिरने से हो गयी थी। उक्त मामले में इस न्यायालय ने माना कि मुआवजे के निर्धारण के सिद्धांत को एम.वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची और माता-पिता की उम्र पर विचार करते हुए उपयुक्त गुणक को लागू करते हुए देखा जा सकता है। यह भी कहा गया है कि भविष्य की संभावनाओं के संबंध में दावा को न्यायालयों द्वारा प्रदर्शन और स्कूल की प्रतिष्ठा के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए था। उक्त मामले में, लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2001)8 एससीसी 197 और एम.एस. ग्रेवाल और अन्य बनाम दीप चंद सूद और अन्य (2001)8 एससीसी 151 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का पालन किया गया है और वृद्धि की गई थी। लता वाधवा (ऊपर) के मामले में, यह स्पष्ट किया गया था कि 5 से 10 और 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विभाजित करते हुए मुआवजा दिया जा सकता है। यह माना जाता है कि मुआवजे का ऐसा अनुदान माता-पिता को संभावित नुकसान का दावा करने से नहीं रोकेगा और यह वैध होगा। इस न्यायालय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रसिद्ध मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर भी भरोसा किया टैफ वेले रेलवे बनाम जानकिंस 1913 एसी 1 , जिसमें लॉर्ड एटकिंसन ने इस प्रकार देखा:

"... केवल इतना आवश्यक है कि मुकदमा करने वाले व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ की उचित अपेक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि इस अपेक्षा का अस्तित्व तथ्य का एक अनुमान है - तथ्य का एक आधार होना चाहिए जिससे यथोचित रूप से खींचा जा सकता है; लेकिन मैं इस प्रस्ताव से अपनी जोरदार असहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि दो तथ्य जिनके बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, पहला, कि मृतक ने अतीत में पैसा कमाया और दूसरा, उसने वादी के समर्थन में योगदान दिया। ये निस्संदेह गर्भवती साक्ष्य के टुकड़े हैं, लेकिन वे केवल सबूत के टुकड़े हैं; और आवश्यक निष्कर्ष, मुझे लगता है, उनके अलावा और उनसे अलग परिस्थितियों से निकाला जा सकता है।

10. इस प्रकार अवलोकन पर भरोसा करते हुए, यह कहा जाता है कि बच्चे की मृत्यु के मामले में मुआवजे के निर्धारण के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने के स्थान पर, इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। एम.एस. ग्रेवाल (ऊपर), एक नदी में डूबने के कारण 14 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। इस

न्यायालय ने यह देखते हुए कि छात्र उच्च मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से संबंधित थे, हालांकि 5,00,000 / इसके बाद के मामले में किशन गोपाल (ऊपर), 19.7.1992 को हुई सड़क दुर्घटना में लगभग 10 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, इस न्यायालय ने एम.वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची से प्रस्थान किया और 15,000/- रुपये के स्थान पर 30,000/- रुपये की कल्पित आय को स्वीकार किया, यह सादृश्य लागू करते हुए कि रुपये के मूल्य में 1994 से भारी गिरावट आई है जब एम.वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 15000/- रुपये की अनुमानित आय तय की गई थी। हालांकि, अनुमानित आय को 30,000/- रुपये और माता-पिता की आयु अर्थात 36 वर्ष के अनुसार स्वीकार करते हुए, निर्भरता की हानि की गणना 15 के गुणक को लागू करते हुए 4,50,000/- रुपये पर की गई थी और पारंपरिक शीर्षों के तहत 50,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी, जिसमें कुल 5,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया था।

11. हाल ही में के मामले में कुरवन अंसारी @ कुरवन अली और एक अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और एक अन्य (2022) 1 एससीसी 317, जिसमें 6.9.2004 को एक सड़क दुर्घटना में लगभग 7 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, इस न्यायालय ने कल्पित आय को 25,000/- रुपये मानते हुए, 15 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता के नुकसान की गणना 3,75,000/- रुपये और पारंपरिक शीर्षों में 55,000/- रुपये जोड़कर 4,70,000/- रुपये का मुआवजा दिया।

12. पूर्वगामी निर्णयों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि बाल मृत्यु के मामलों में, मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट 15,000 रुपये की अनुमानित आय को उस तारीख से धन और रुपये के मूल्य के अवमूल्यन के कारण बढ़ाया गया है, जिस दिन एम.वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची पेश की गई थी और उक्त अनुमानित आय को 30,000 रुपये माना गया था। किशन गोपाल (ऊपर) और रु. 25,000/- में कुरवान अंसारी (ऊपर) क्रमशः 10 और 7 वर्ष के आयु वर्ग में।

13. इस प्रकार उक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में बच्चे की उम्र को देखते हुए अर्थात 12 वर्ष, के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को देखते हुए किशन गोपाल (ऊपर) के तथ्यों पर उपयुक्त रूप से लागू होते हैं वर्तमान मामला में। मृतक की मां के मौखिक बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक एक मेधावी छात्र था और एक निजी स्कूल में पढ़ता था। इसलिए, भविष्य की संभावना सहित 30,000 रुपये की अनुमानित आय

को स्वीकार करना और 15 के गुणक को लागू करना। सरला वर्मा (ऊपर), निर्भरता का नुकसान रु. 4,50,000/ - होता है और यदि हम पारंपरिक मदों में रु. 50,000/- जोड़ते हैं, तब मुआवजे की कुल राशि 5,00,000/- रुपये बनती है। एम.ए.सी.टी. के फैसले के अनुसार, 1,50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय ने दावा याचिका के मूल्य तक इसे बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया है। हमारे विचार में, मुआवजे की उक्त राशि यहां ऊपर की गई गणना को देखते हुए न्यायसंगत और उचित नहीं है। इसलिए, हम कुल मुआवजे को 5,00,000/- रुपये निर्धारित करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को कम करने पर यानी 2,00,000/- रुपये की बढ़ी हुई राशि 3,00,000/- रुपये बनती है।

14. इस स्तर पर, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के अनुसार नागप्पा बनाम गुरदयाल सिंह और अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2003) 2 एससीसी 274 के मामले में यह पाया कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि अधिकरण/न्यायालय इस प्रकार दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा नहीं दे सकता है। ट्रिब्यूनल/कोर्ट को 'न्यायसंगत' मुआवजा देना चाहिए जो रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों पर भरोसा करते हुए तथ्यों में उचित हो। इसलिए, दावा याचिका में किया गया कम मूल्यांकन, यदि कोई हो, दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा देने में बाधा नहीं होगी।

15. तदनुसार, इस अपील को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि में 3,00,000/- रुपये की वृद्धि की गई है। मुआवजे की कुल राशि 5,00,000/- रुपये होगी। बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका की तारीख से वसूली तक @ 7% प्रति वर्ष ब्याज होगा। देय राशि का भुगतान प्रतिवादी नंबर 4 - यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

16. पक्षकारों को अपनी लागत वहन करनी है। अपील की अनुमति दी।

<u>यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>